PETITION RE. GRIEVANCES AND DEMANDS OF CATAMARAN AND COUNTRY BOAT FISHERMEN

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diomond Harbour): Sir, I beg to present a petition signed by Sri Matanhy Saldanha, General Secretary, Goenchea Ramponkaracho Ekvott, Goa and others regarding grievances and demands of catamaran and country boat fishermen.

12.27-1/2 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED DECISION TO IMPORT COPRA AND COCONUT OIL

SHRI V M SUDHEERAN (Alleppey): With your permission, I rise to mention the following matter of urgent public importance in the House.

The reported decision of the Union Government to import copra and coconut oil will have disastrous consequences for Kerala's economy in general and for the lakhs of coconut growers in particular. Kerala contributes 78 per cent of the coconut production in the country The total coconut cultivation in our country is 11 lakh hectares. But of which Kerala cultivates 8 lakh hectares of coconut. The total milling copra produced in India is about 3,43,000 tonnes; out of which Kerala's contribuation is 3,34,000 tonnes. This clearly shows that coconut is the main cash crop of Kerala in which 80 lakhs of people are engaged. They are small growers. Kerala produces the main portion of the cash crops and spices to meet the requirements of the country and for earning foreign exchange. Any decision to import copra and coconut oil will definitely bring down the prices of coconut nuts and coconut oil, which will adversely affect the small coconut cultivators. This will shatter the economy of Kerala. It is evidently convinced that we produce 3,42,000 tonnes milling copra, which is adequate to meet the domestic requirements in our country. So, there is no justification for the decision of the Union Government to import copra and coconut oil while our country is self-sufficient to meet the domestic demands. I would like to urge upon the Union Government to reconsider and revoke the reported decision to import copra and coconut oil so as to save the lakhs of coconut cultivators and the economy of Kerala.

(ii) REPORTED BLOCKING OF RIVER BHAGIRATHI BECAUSE OF A LANDSLIDE

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मै नियम 377 के अधीन भागीरथी के प्रवाह में अवरोध क सम्बन्ध मे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य देना चाहता हू ।

समाचार-पत्रो की खबरो के अनुसार उत्तर-काशी जिले मे उत्तरकाशी से लगभग 40 किलो मीटर दूर गगनाणी के पास चट्टान टूटकर गिर जाने से भागीरथी का प्रवाह रुक गया है और वहां एक कृत्रिम झील बन गई है । इसमे उस क्षेत्र मे हरसिल की बस्ती डूब गई है । परन्तु उससे भी अधिक खतरा उत्तरकाशी से इलाहाबाद तक के गगा के किनारे के क्षेत्रों के लिये हो गया है ।

उत्तरकाशी नगर खाली कराया जा चुका है । 20 वर्ष पहले भी इस क्षेत्र में लुहारीनाग नामक स्थान पर इस प्रकार की झील बन गई थी । हिमालय की चट्टानें बहुत कमजोर हैं और वहां पर सडक निर्माण तथा जगलो की बेरहमी से कटाई के कारण भूस्खलन एक नियमित घटना हो गई है ।

आठ वर्ष पूर्व भागीरथी की दूसरी सहायक अलकनंदा में भयंकर दुर्घटना हुई थी, जिसका प्रभाव गंगा नहर पर भी पडा था । पिछले वर्ष पिठौरागढ़ जिले के तवाघाट नाम स्थान पर भूस्खलन से 44 व्यक्ति मर गये थे । हिमालय में ये दुर्घटनाये गलत विकास नीतियो के कारण हो रही है, क्योकि इन विकास कार्यों से वहां पर प्रकृति के साथ अनावश्यक छेडछाड़ की जा रही है । टिहरी में भागीरथी पर एक विशाल बांध वहां की जनता और स्वतंत्र वैज्ञानिकों की राय के खिलाफ केवल सबसे ऊंचा बांध बनाने के राष्ट्रीय अहकार की तुष्टि के लिये सशस्त्र पुलिस के सरक्षण में बन रहा है । इस प्रकार की योजनायें पूरे देश के लिए भयंकर तबाही का कारण बन सकती हैं । अत: सरकार को हिमालय क्षेत्र के विकास को एक 100 वर्षीय योजना वहां के प्राकृतिक संतुलन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनानी चाहिये ।